

(Shri Chintamani Jena)

has to finance it but after a lapse of more than 4 years, no progress has yet been made on this issue for which lakhs of farmers are at a stage of frustration and are in a great concern. The drainage schemes which was sent to the Central Water Control Board is yet to be cleared up by them.

I would, therefore, draw the immediate attention of the hon. Minister for Irrigation to this problem for rendering the long pending problem to be solved, specially when the rainy season has started and high flood is expected at any moment.

(ii) **RESUMPTION OF OIL EXPLORATION IN PILIBHIT DISTRICT OF UTTAR PRADESH**

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीली-भीत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत एक लोक महत्व के प्रश्न को उठा रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तेल एवं प्रार्थित गैस आयोग ने सर्वेक्षण के आधार पर तेल की खोज के लिए जिले में दो स्थान चुने। परन्तु पिछले वर्ष केवल एक स्थान पर ही आधी खुदाई करके कार्य बन्द कर दिया गया। दूसरे स्थान को छुआ तक नहीं गया। जहां खुदाई बन्द की गई उसका कारण कठोर चट्टान का आना बताया गया जबकि विभाग के पास बहुमूल्य व उत्तम कोटि के ड्रिलिंग के उपकरण मौजूद हैं। यदि किसी कारण एक स्थान पर ड्रिलिंग बन्द किया गया तो दूसरे स्थान पर कार्य आरम्भ करना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके व करोड़ों रुपया खर्च करने के पश्चात् व भूगर्भ वज्ञानिकों की रिपोर्ट

के आधार पर दोनों स्थानों पर खुदाई न करके खुदाई के समस्त उपकरण दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं जबकि पीली भीत के दोनों स्थानों पर तेल मिलने की पूर्ण सम्भावना है। माननीय पेट्रोलियम मंत्री इन उपकरणों को कृपया दूसरे प्रदेशों में न भेज कर पीलीभीत के दोनों स्थानों पर तेल की खोज करायें।

(iii) **REPORTED NON-SUPPLY OF RAW MATERIAL BY STC, SAIL AND INDIA PETROLEUM TO WEST BENGAL**

SHRI SUDHIR GIRI (Contd.): A critical situation has arisen in West Bengal because of the non-performance of their respective obligations by three Central Government agencies, viz., The Indian Petroleum, the State Trading Corporation and the Steel Authority of India. The West Bengal Government deposited in advance with them an amount of Rs. 21.21 crores for the supply of raw materials, but they have neither supplied the materials ordered for nor are they refunding the money in spite of repeated demands. An apprehension has, therefore, gained ground that these units have invested the amount of Rs. 21.21 crores in other fields.

I would, therefore, request the hon. Minister to kindly take remedial measures immediately in view of the fact that the economic development of West Bengal is being hampered to a great extent for want of materials.

(v) **PURCHASE OF JUTE BY JUTE CORPORATION OF INDIA IN PURNEA AND SAHARSA DISTRICTS OF BIHAR**

श्री तरेश सह (विक्रमगंग): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। फसल तैयार है। भारतीय जूट निगम द्वारा अभी तक सपोर्ट प्राइस पर जूट खरीदने की नीति निर्धारित नहीं हुई है। किसानों को बहुत कम दामों (डिरेट्रेस प्राईस) पर प्राइट ट्रेड के यहां मजबूरी में अपनी